

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग
प्रेमनगर, देहरादून।

उद्घान एवं रेशम अनुभाग:-2

देहरादून: दिनांक 16 मई, 2008

विषय:-वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-34/रेशम/तक0अनु0/बजट/2008-09 दिनांक 03 अप्रैल, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर की चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्न विवरणानुसार रू0-1100.00 हजार (रू0 ग्यारह लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किरतों में किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा।
- 2- उक्त व्यय करते समय प्रचलित सुसंगत विभागीय प्राविधानों/निर्देशों तथा मितव्ययिता सम्बन्धी व्यवस्थाओं की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 3- व्यय हेतु उत्तराखण्ड अभिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन)/नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (आय व्यय सम्बन्धी नियम) आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 4- अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशप्लॉ निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
- 5- निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।
- 6- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 7- व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।
- 8- व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

- 9- योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा-निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- 10- लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 11- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 12- यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम की कार्ययोजना भी तैयार की जाय, जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।
- 13- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी और सब्जियों की फसलें-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-83(P)/XXVII-4/2008, दिनांक-14मई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

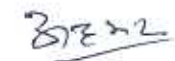
(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या-436/XVI/08/7(33)/08, तददिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अहमद अली)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-436 / XVI / 08 / 7(33) / 2008 दिनांक: / 6 मई, 2008 का संलग्नक
 रेशम विकास विभाग की वर्ष 2008-09 की अनुदान संख्या-30 की राज्य सेक्टर आयोजनागत योजनाओं
 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का योजनावार/मदवार
 विवरण।

अनुदान सं०-30 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत 118-बागवानी और सब्जियों की फसलें 02-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (कमशः)			
			(धनराशि हजार रु० में)
क०सं	योजना/मद	वर्ष 2008-09 हेतु बजट प्राविधान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	0211-सहकारी समितियों को रेशम विकास पूंजी 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	300	300
2	0212-जैविक रेशम विकास 02-मजदूरी 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 31-सामग्री और सम्पूर्ति	100 20 30 250	100 20 30 250
	योग : 0212	400	400
3	0213-वृक्षारोपण विकास योजना 02-मजदूरी 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 31-सामग्री और सम्पूर्ति	100 100 200	100 100 200
	योग : 0213-	400	400
	महायोग (कमांक 1 से 3 तक)	1100	1100

(रुपये ग्यारह लाख मात्र)


 (अर्जुन सिंह)
 अपर सचिव